

हरिजनसेवक

दो आना

(स्थापक : महात्मा गांधी)

भाग १५

सम्पादक : किशोरलाल मशरुवाला

सह-सम्पादक : मगनभाभी देसायी

अंक २५

मुद्रक और प्रकाशक
जीवणजी दासभाभी देसायी
नवजीवन मुद्रणालय, अहमदाबाद-९

अहमदाबाद, शनिवार, ता० १८ अगस्त, १९५१

वार्षिक मूल्य देशमें ₹० ६
विदेशमें ₹० ८९ शि० १४

डांगे-विनोबा पत्रव्यवहार

[कम्युनिस्ट नेता श्री० अ० डांगे और श्री विनोबाका यह पत्रव्यवहार दैनिक पत्रोंमें प्रकाशित हो चुका है। कम्युनिस्टोंके प्रति सर्वोदयका मनोभाव और खासकर हैदराबाद तथा सामान्यतः दूसरी जगहोंमें जमीनका सवाल समझनेके लिये वह महत्वपूर्ण है, जिसलिये उसे यहां दिया जा रहा है। —सम्पादक]

केन्द्रीय कार्यालय,
हिन्दुस्तानकी कम्युनिस्ट पार्टी,
१९०-बी, खेतवाड़ी मेन रोड,
बम्बयी ४
ता० ७ जून, '५१

श्री विनोबा भावे,
गांधी आश्रम, वर्धा

प्रिय श्री विनोबा भावे,

मुझे आपसे कभी प्रत्यक्ष मिलनेका अवसर तो नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन मैं सोचता हूँ कि आप मेरे बारेमें जितना तो जानते ही हैं कि परिचय देनेकी आवश्यकता न रह जाय।

मैं आपको यह पत्र आपकी तेलंगाना-यात्रा और हैदराबाद जलमें बन्द हमारी पार्टीके कभी सदस्योंके साथ आपकी मुलाकातके सिलसिलेमें लिख रहा हूँ। मैंने सुना है कि आपने उनसे आम तौर पर 'तेलंगाना-आन्दोलन' के नामसे मशहूर सवाल पर और कुछ दूसरी बातों पर, जिनका ताल्लुक उनकी रिहाजीसे था, उनकी राय जानना चाही थी। अपने एक साथीसे, जो हालमें ही छोड़ा गया है और जो आपकी मुलाकातके समय वहां हाजिर था, मैंने सुना है कि उन लोगोंसे मिलनेमें आपका अद्देश्य उनका परिवर्तन करने या खुद परिवर्तित हो जानेका था। और जो प्रश्न आपने उनके सामने पेश किया, वह यह था कि आन्तरराष्ट्रीय परिस्थितिमें हुआ फर्क, युद्धकी आशंका और अन्न-संकटसे उत्पन्न देशकी हालत, आदि बातोंको नजरमें रखकर उन लोगोंने, जिन्होंने तेलंगानामें हिंसाको एक पद्धतिके रूपसे अपनाया, जिस सवाल पर फिरसे विचार किया है या नहीं; नहीं किया है तो वे फिरसे विचार करनेके लिये तैयार हैं या नहीं? क्या उनमें से किसीको अंसा लगता है कि कमसे कम मौजूदा परिस्थितिमें हिंसा योग्य नहीं है? आप उनसे जिन सवालों पर खुले दिलसे बातचीत करना चाहते थे।

मुझे मालूम हुआ है कि हमारे साथी जिन सवालों पर आपसे बातचीत नहीं कर सके। अतः जेलकी जिन तकलीफदेह परिस्थितियोंमें उन्हें रहना पड़ता था, आपके सामने सिर्फ उनका विजहार करके उन लोगोंने सन्तोष माना।

मैं अुम्मीद करता हूँ कि यह तो आपको स्पष्ट हो ही गया होगा कि आपके द्वारा अुठाये गये सवालों पर वे क्यों नहीं चर्चा

कर सके। अुसका कारण यह नहीं था कि अुन्हें आपके प्रति अनादर है, या अुन अुसूलोंमें विश्वास नहीं है, जिन पर अमल करनेके कारण वे जेल गये हैं। पार्टीके शिष्ट सदस्यों या मित्रोंकी तरह अुन्होंने यह ठीक नहीं समझा कि वे कम्युनिस्ट पार्टीके सिद्धान्तों और नीतिके औचित्यके बारेमें गांधीवादके आपके जैसे प्रमुख अनुयायीका समाधान करनेका अुन अपने अुपर अुठायें। अुन्होंने जिस कामको बाहरकी पार्टी पर छोड़ना ठीक समझा।

जिसके सिवाय, अंग्रेजी सत्ताके खिलाफ हमारे संघर्षके पुराने इतिहासके अुदाहरणोंसे, यह स्पष्ट है कि जेलकी चहारदीवारीके भीतर कैदियोंसे सिद्धान्तों और नीति पर जिस किस्मकी बातचीत अुन कैदियोंको तथा बाहरके दूसरे सदस्योंको भी ऐसी अुलझनोंमें डालती है, जिन्हें जेलवासियोंको टालना ही अच्छा है। जिसलिये ये समाचार जब मुझे मिले, तो मैंने आपको लिखना अुचित्त समझा।

आरम्भमें ही मैं आपको कह दूँ कि हमारे लोगोंसे जेलमें और तेलंगानाके जिलोंमें मिलनेके आपके सद्भावकी मैं कद्र करता हूँ। मेरा खयाल है कि जिस यात्रामें आपका मुख्य अुद्देश्य वहांकी जनता और अुनके जेलमें बन्द या बाहर छिपकर रहे नेताओंके लिये फिरसे शान्तिमय जीवन बितानेकी परिस्थितियां निर्माण करनेका था। मैं आशा करता हूँ कि आप यह मानेंगे कि हमारी पार्टीका भी कोई दूसरा लक्ष्य नहीं है। सवाल यह है कि यह कैसे सिद्ध किया जाय?

आपकी बातचीतसे आप अंसा समझते मालूम होते हैं कि कम्युनिस्टोंने हिंसाको अपनाकर लोगोंको भी अपनी मांग हासिल करनेके लिये वैसा ही करनेको बहकाया; बस तेलंगानाकी गड़-बड़ीका यही कारण है। आप यह मानते देखते हैं कि एक बार हमने 'हिंसा' का त्याग किया कि शांति हो जायगी।

क्या आप समझते हैं कि जिस तरहकी बहससे कोअी अच्छा परिणाम आ सकेगा? आपने खुद ही यह प्रत्यक्ष कर दिया है कि तेलंगानामें मुख्य सवाल यह नहीं है कि हम लोग हिंसक हैं या अहिंसक। अगर अंसा होता, तो आपने अपनी यात्राका कार्यक्रम सिर्फ लोगोंको अहिंसके गुण बताने और कम्युनिस्टोंकी तथाकथित हिंसाकी बुराअी दिखाने तक ही सीमित रखा होता।

लेकिन आपने तो अपना काम यहीं तक सीमित नहीं रखा। अखबारोंकी खबरोंसे तो मैंने यह समझा है कि आप जिस बातसे वाकिफ हैं कि वहां मुख्य सवाल किसानका है, — अुस किसानका जिसके पास जमीन नहीं है, या है तो बहुत थोड़ी है और जो लगान और महसूलोंकी अुंची दरों, कर्ज और बेगार तथा जिनका समर्थन करनेवाली शासन-प्रणालीके बोझसे पिसा जा रहा है। जिसलिये तो आपने अंके भू-निधि जैसी चीज शुरू करना और बेजमीन किसानोंको जमीन देना ठीक समझा। मेरा विश्वास है कि आपने जिस बातको समझ लिया और बंता दिया है कि मुख्य

सवाल जमीनका है और उसे सुलझाये बिना हमारे देशकी समस्या हल नहीं हो सकती।

अगर आपका निष्कर्ष यही है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं और मेरे साथी उस पर आपके साथ एकमत हैं। और जितने वर्षों तक तेलंगानाकी लड़ाई किसी मुख्य अदृश्यको हासिल करनेके लिये होती रही है। जब तक किसानको जमीन नहीं दी जाती, महंगे लगान, ब्याज और करोंका बोझ दूर नहीं किया जाता, जब तक उसे अिनसे और बेगारसे नष्ट होनेसे बचाया नहीं जाता, तब तक उसके लिये जीवनकी शान्तिमय परिस्थितियाँ असंभव हैं। अगर उसकी ये मांगें पूरी नहीं होतीं, तो फिर वह उस लाठी और बन्दूकको छोड़ भी दे, जिसे उसने संभवतः अपनी रक्षाके लिये अुठाया होगा, तो भी उसे जीवनकी शान्तिमय परिस्थितियाँ नहीं मिलेंगी। हाँ, उसे कन्नकी शान्ति मिल सकती है। लेकिन उस शान्तिमें, अगर वह शान्ति है तो, जनताको कौनसा जीवन और कौनसी समृद्धि मिल सकती है?

आजकल हिन्दुस्तानमें हरएक आदमी यह मानता है कि अगर हम अपनी अन्न-समस्या या कोअी भी समस्या हल करना चाहते हैं, तो किसानको जमींदारी प्रथाके बोझसे मुक्त कर देना चाहिये। सिर्फ जमींदार ही उसे नहीं मानते। और जब किसान गरीबी और भूखसे तंग आकर अघोर हो जाता है और जमीन पर कब्जा करनेका निर्णय करता है तथा जमींदार और साहूकारको अपना विनाश करनेसे रोकता है, तो राज्यका सारा कोप उसके सिर पर बरसने लगता है; क्योंकि कानूनने उसे जमीन पर मेहनत करने और अपना पेट भरनेका अधिकार नहीं दिया है। अंसी स्थितिमें अगर कानून जीवनके विरोधमें खड़ा होता है, तो दोनोंमें बड़ा कौन है? मुझे विश्वास है कि आप यह मानेंगे कि जिन्दगी, लाखों-करोड़ोंकी जिन्दगी, कानूनसे बड़ी है; क्योंकि यहां कानून लाखोंकी जिन्दगीके अनुकूल नहीं है, सिर्फ मुट्ठीभर साहूकारोंके ही हितमें है।

तेलंगानामें ठीक यही हुआ है। शोषणकी अेकदम पुरानी और सड़ी-मली व्यवस्थामें रहनेवाले वहांके किसानों पर आजादी और लोकशाहीके युद्धोत्तर ज्वारका असर हुआ। वे अुत्साहित हुए और सन् १९४६ में अुन्होंने जमींदारोंको अूँचा लगान देना या अुनकी बेगार कूरना बंद करनेका निश्चय किया। और जिनके पास जमीन नहीं थी, अुन्होंने बेकार पड़ी हुई जमीन ले ली और उस पर अन्न पैदा करनेके लिये मेहनत करना शुरू कर दिया। जिनकी जमीनें लोअी जमींदारों और साहूकारोंने छीन ली थीं, वे वापिस आये और अुन्होंने मांग की कि वे अपनी जमीन जोतेंगे और अपना और अपने देशका पेट भरेंगे। यह सब जो हुआ वह हमारे देशके अुन संघर्षोंकी दीर्घ परम्पराके अनुसार ही था, जिन्हें हमने बीते हुए जमानेमें अुत्तरप्रदेश, बिहार और बारडोलीमें देखा था। यह नेहरू-सरकारको दिल्लीकी गादी मिली, अुसके बहुत पहलेकी बात है। ये हमारे वही पुराने अदम्य किसान जीवन और जीविकाके लिये अपनी परंपरागत लड़ाई लड़ रहे थे।

किसानोंकी अिस न्यायोचित मांगका जमींदारों और सरकारने क्या अुत्तर दिया? अुन्होंने किसानों पर कहर ढानेके लिये रजाकारोंकी खानगी और राज्यकी सरकारी फौज छोड़ दीं, ताकि जमींदारोंका किसानोंको जमीन न देने तथा अपना लगान वसूल करते रहनेका अधिकार जबरदस्ती कायम रखा जाय।

मुझे आपको पूरी दास्तान सुनानेकी जरूरत नहीं मालूम होती। आपने सरकारकी ओरसे तो अुसे सुन ही लिया है। तेलंगानाके किसानोंको क्या कहना है, वह दुहरानेकी मेरी अिच्छा नहीं है। अुनमें से सैकड़ों पुरुषों, स्त्रियों और बच्चोंको यातनायें दी गयीं हैं और मार डाला गया है या जेलमें ठूस दिया गया है; और यह सब अिसलिये कि वे जमीन और जीविकाके अपने अधिकारकी रक्षा करत थे।

मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप जरा ठहरें और सोचें कि अिन लाखोंमें ये यातनायें सहनेकी शक्ति कहाँसे आयी। कोअी विचारधारा — वह हिंसाकी हो या अहिंसाकी — और कोअी भी पार्टी — वह आपकी हो या हमारी — गोलियाँ, यातनायें और घेरा सहने और अुसका वीरतापूर्वक मुकाबला करनेकी शक्ति लोगोंको नहीं दे सकती, अगर अुन्हें अिसका विश्वास न हो गया हो कि वे जो कुछ कर रहे हैं अुससे अुनके जीवनका सवाल हल होनेवाला है।

तेलंगाना-आन्दोलनको चलते हुअे आज पांच साल हो गये। यह अेक अच्छा संकेत है कि अब आप जैसे लोगोंने अिस सवाल पर ध्यान देना शुरू किया है। मैं अिस आंदोलनसे सम्बद्ध दूसरे सब सवालोंने नहीं आना चाहता। लेकिन सवालकी जड़को तो आपने खुद ही देख लिया मालूम होता है। और वह जड़ यह है कि किसान पर जुल्म हो रहा है, अुसे जमीन चाहिये और अुस व्यवस्थासे मुक्ति चाहिये, जो अिस जुल्मको बल देती है और चलाती है।

हम यहां हिंसा और अहिंसा या कानून और व्यवस्था की बहसमें नहीं पड़ेंगे; क्योंकि अगरचे हमारे खिलाफ यह आरोप किया जाता है, फिर भी हिंसा और कानूनभंग कोअी हमारा मान्य सिद्धान्त या तत्त्वज्ञान नहीं है। अिस बहसमें अगर हम अुतरें, तो मुख्य सवाल अेक ओर रह जायगा और हम अेक फिजूलकी अुलझनमें फंस जायेंगे। मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि तेलंगानाका हरअेक किसान और हरअेक कम्युनिस्ट, अगर कहीं वह बंदूक लेनेके लिये मजबूर हुआ है, तो बंदूक छोड़कर हल हाथमें लेनेके लिये और अपने सिर पर मंडराती मौतके संकटको शान्तिमय परिश्रमके लाभोंसे बदलनेके लिये हमेशा तैयार है; हाँ, शांतिका आश्वासन अुसे मिलना चाहिये। लेकिन पिछले पांच वर्षोंसे अिस आश्वासनकी बजाय सबके सब अुसे नेस्तनाबूद करनेकी धमकियाँ ही देते रहे हैं। हो सकता है कि कभी-कभी राज्यका बल जनबलसे ज्यादा जोरदार सिद्ध हो, लेकिन अिस तरह किसी जनताको सदाके लिये कमी कुचला जा सका है?

कहा जाता है कि किसानोंने हमारी सलाहसे जमीन पर कब्जा करके, लगान और ब्याज देनेसे अिनकार करके और अिन जमींदारोंके लिये बेगार करना छोड़कर कानूनका भंग किया है। लेकिन आप देख सकते हैं कि अगर कानूनको कुछ अिनेगिने लोगोंका अुनुचर नहीं बनना है, तो कानून जीवनकी मांगके अनुसार हो यही ज्यादा न्यायसंगत है, बनिस्वत अिसके कि लाखों लोगोंको कानूनकी आज्ञा मानने और कुछ अिने-गिने लोगोंके हितमें रहनेके लिये अिसलिये मजबूर किया जाय कि अिस चीज पर अेक पुराने और सड़े-गले कानूनकी मुहर है। अुदाहरणके लिये, कुछ जमींदार आपके पास आये और जरूरतमन्द किसानोंको बांटनेके लिये कुछ हजार अेकड़ जमीन आपको यह बतानेके लिये दें कि अुनके हृदय बदल गये हैं — अिस बातकी प्रतीक्षा करनेके बजाय क्या यह ज्यादा आसान नहीं होगा कि पिछले पांच सालोंमें लाखों किसानोंने जिस लाखों अेकड़ जमीन पर मेहनत की है, जिन्दगी लगायी है और फसल पैदा की है, वह कानून बनाकर अुनको ही दे दी जाय? या यह होता रहे कि अेक ओर तो राज्यकी सेनायें हमारे किसानों पर गोलियाँ चलाती रहें, अुन्हें जमीनसे खदेड़ती रहें, और बरबाद करनेवाले लगान देनेको मजबूर करें, और दूसरी ओर आप अुन्हें बांटनेके लिये भू-निधि अिकट्टी करते हुअे धूमें? अिस प्रक्रियामें क्या तुक और तर्क हो सकता है?

मुझे खेद है कि मैंने अपनी बात सुनानेमें आपका बहुतसा वक्त ले लिया है। लेकिन मुझे लगा कि जब आपकी अूँचाअी और गौरवके अिकतिने तेलंगाना जाना और अिस समस्याका प्रत्यक्ष अध्ययन करना तय किया है, तो मैं भी आपके पास पहुंचूँ और

असको कोशिश कलं कि क्या अुस अुद्देश्यको हासिल करनेका, जो कि आपकी दृष्टिमें भी है, कोअी आसान और जल्दीका हल नहीं मिल सकता। और वह अुद्देश्य तो यही है कि तेलंगानामें शांतिकी परिस्थितियां अुत्पन्न की जायं, किसानोंको जमीन दी जाय, वहांकी जुल्मी जमींदारी प्रथाकी जगह अेक प्रगतिशील और सबको सुखकर व्यवस्था कायम की जाय, और अुन हजारों कम्युनिस्ट या गैर-कम्युनिस्ट लोगोंकी जान बचाओ जाय, जिन्हें हमेशा मृत्यु या कारावासका डर बना रहता है।

जेलमें बन्द जिन साथियोंसे आप मिले, अुनके सामने बड़ी बाधाये थीं, अिसीलिअे मैंने आपको लिखनेका निश्चय किया।

जैसा कि आपने हमारे साथियोंसे कहा था, 'परिवर्तन करने या परिवर्तित होने' के लिअे मैं आपसे जरूर खुद ही मिला होता। लेकिन बदकिस्मतीसे ब्रम्बजी सरकारने मेरे खिलाफ अेक आरोप लगा रखा है, और यदि अदालतकी मदद न मिले तो सर्वव्यापी 'प्रतिबन्ध-कानून' (Detention Act) की मददसे वह मुझे जेलमें ठूसनेकी राह देख रही है। अिसलिअे फिलहाल तो मैं आपसे मिलने और आपके सामने सारी बातें रखनेमें असमर्थ हूं।

लेकिन अगर आपको लगे कि मैं तेलंगानाकी समस्याका कोअी अैसा हल बूढ़नेमें, जिससे कि वहांकी जनताको शान्ति और सुख मिले, किसी तरहकी मदद कर सकता हूं, तो मैं अिस सेवाके लिअे तैयार हूं।

यदि आप जवाब देनेकी बात सोचें, तो अपना अुत्तर अूपरके पते पर भेज सकते हैं।

(अंग्रेजीसे)

आपका,

श्री० अ० डांगे

परंधाम, पवनार

ता० ११-७-५१

श्री डांगे,

विशेष सावधानीके साथ भिजवाया हुआ आपका सविस्तर पत्र मुझे मिल गया है। पत्रकी ध्वनि मुझे भली लगी।

जमीनका प्रश्न हल होना चाहिये और अुसमें कानूनकी भी मदद मिलनी चाहिये, अिस पर कोअी बहस नहीं है। अिस विषय पर मैं जगह-जगह बोला भी हूं।

तेलंगानाके प्रश्नका सब पहलुओंसे जितना अभ्यास हो सका, मैंने किया है। और अिसकी भरसक सावधानी रखी है कि विचारके किसी पहलूकी अुपेक्षा न हो। मैं अिसी परिणाम पर आया हूं कि यह प्रश्न प्रेमसे, विश्वाससे और शांतिसे हल हो सकता है।

हिंसा और अहिंसाकी तात्त्विक चर्चामें मैं पड़ा नहीं और न पड़ना चाहता हूं। लेकिन रजाकारोंका जमाना बीतनेके बाद भी जिस तरहका हिंसाकांड तेलंगानामें चलाया जाता रहा, अुसका किसी भी तरह बचाव किया जा सकता है, अैसा मुझे नहीं लगता। अुसके पहले हुआ हिंसाका विचार मैं नहीं करता। लेकिन अुसके बाद जो हिंसा जारी रखी गयी, अुसमें मुझे बड़ा विचार-दोष नजर आता है।

मैं अिस निश्चित मत पर आया हूं कि हिन्दुस्तानकी कम्युनिस्ट पार्टीके लिअे रतीभर भी आनाकानी किये बिना अपनी मौजूदा नीति बंदलना अत्यंत आवश्यक है। अुसमें गरीब जनताका भी हित है और कम्युनिज्मका भी।

जमीनका प्रश्न हल करनेमें मुझसे जितनी मदद बनेगी, अुतनी जो लोग अिस प्रश्नको हल करनेके लिअे व्याकुल हैं अुन्हें मिलेगी ही।

आपको भूमिगत रहना पड़ रहा है, अिसका मुझे दुःख है। मैं तो यह चाहता हूं कि सब लोग विशिष्ट सीमामें रहकर आजादीके साथ अपना काम कर सकें।

भेंटका सुयोग जब आयेगा, तब विस्तारपूर्वक चर्चा हो सकेगी। (भराठीसे)

बिनोबाके प्रणाम

कोठ-कामकी तालीम

वर्धाका महारोगी सेवा मंडल गांधी स्मारक निधिअे आश्रयमें साधारण कार्यकर्ताओंके लिअे दत्तपुर कुष्ठ आश्रममें अेक तालीम केन्द्र शुरू करना चाहता है। अुन्हें अिस तरहसे तालीम दी जायगी कि वे—संभव हो तो डॉक्टरी मददसे—कोठी बस्तीका संगठन और संचालन कर सकें। लेकिन अगर डॉक्टरोंकी मदद न मिल सके, तो भी तालीम पाये हुए सामान्य कार्यकर्ताओंमें स्वीकृत पद्धतिके अुनुसार बस्तियां चलानेकी योग्यता होनी चाहिये।

शिक्षा सम्बन्धी योग्यता: प्रवेश प्राप्त करनेके लिअे अुम्मीदवारको कमसे कम अिन्टर सायन्स पास होना चाहिये। भारतकी मान्य डॉक्टरी संस्थाके स्नातकों और मध्यप्रदेशके ग्राम्य मेडिकल प्रेक्टिशनरोंको पहले पसन्द किया जायगा। योग्य मामलीमें महारोगी सेवा मंडलके संचालक बोर्ड द्वारा अिसमें अपवाद किये जा सकेंगे।

अुमर: अुम्मीदवारकी अुमर २१ से ४० के बीच होनी चाहिये। विशेष मामलोंमें अिस नियममें अपवाद किया जा सकेगा।

दूसरी शर्तें: अुम्मीदवारोंमें मानव-सेवाकी भावना, अीमान-दारी और अिस तरहके कामकी सच्ची लगन होनी चाहिये। अुम्मीदवारोंमें कोअी लिंगभेद नहीं किया जायगा। लेकिन वे पूर्ण स्वस्थ होने चाहियें और अुनमें किसी भी नयी जगहमें यह काम शुरू करनेकी क्षमता होनी चाहिये।

तालीमका समय: १२ महीनेका होगा।

तालीमका स्थान: मुख्य तालीम दत्तपुर कुष्ठ आश्रममें दी जायगी।

शिक्षाका माध्यम: डॉक्टरी विषय अंग्रेजी माध्यम द्वारा पढ़ाये जायगे। डॉक्टरीसे संबंध न रखनेवाले विषय हिन्दी या मराठी भाषामें पढ़ाये जायंगे।

परीक्षा और प्रमाण-पत्र: पाठ्यक्रम पूरा होने पर लिखित और व्यावहारिक परीक्षा होगी। परीक्षा पास होनेके लिअे ५० प्रतिशत नम्बर पाना जरूरी होगा। अुत्तीर्ण अुम्मीदवारोंको 'लेप्रॉसी ऑर्गेनाइजर' का प्रमाण-पत्र दिया जायगा। जो अुम्मीदवार नियमित रूपसे वर्गमें अुपस्थित रहेंगे और सारी शर्तें पूरी करके शिक्षकोंको सन्तोष दिला सकेंगे, अुन्हींको परीक्षामें बैठनेकी अिजाजत दी जायगी।

रहने-खानेकी व्यवस्था: अभी १० से ज्यादा अुम्मीदवार भरती नहीं किये जायंगे। तालीमके लिअे चुने गये हर अुम्मीदवारको अुसकी व्यक्तिगत जरूरतके मुताबिक ५० से १०० रु० तक छात्रवृत्ति १२ महीने तक दी जायगी। रहनेकी व्यवस्था मुफ्त की जायगी। पहले महीनेका समय प्रयोगकाल माना जायगा। अितने समयमें अगर कोअी अुम्मीदवार तालीमसे लाभ अुठाने योग्य नहीं पाया गया, तो अुसे वापिस जाना होगा।

तालीमके बाद अुम्मीदवारको योग्यताके अुनुसार १५० रु० माहवार पर ५ साल तक अपनी सेवाये देनेका वचन देना होगा। अुम्मीदवार समाज-सेवाका काम करनेवाली किसी संस्थाके मार्फत आवेदन-पत्र भेजें तो ज्यादा अच्छा होगा। जो लोग स्वतंत्र रूपसे आवेदन-पत्र भेजें, अुन्हें अपने कामके बारेमें अैसी जानकारी देनी होगी, जिससे संचालक बोर्डको यह विश्वास हो सके कि वे अपने पांवों पर खड़े रहकर कुष्ठ-निवारणका काम शुरू कर सकते हैं।

अिस विषयका सारा पत्रव्यवहार नीचेके पते पर किया जाय। मंत्रीकी लेखी अिजाजत प्राप्त किये बिना कोअी दत्तपुर न आवे।

दत्तपुर कुष्ठ आश्रम,

मंत्री

नालवाडी, वर्धा

महारोगी सेवा मंडल

७-६-५१

हरिजनसेवक

१८ अगस्त

१९५१

साम्यवादके बारेमें

अस अंकमें दूसरी जगह भारतीय साम्यवादी दलके नेता श्री श्री० अ० डांगे और श्री विनोबाका पत्रव्यवहार प्रकाशित हो रहा है। मैं पाठकोसे अनुरोध करता हूँ कि वे उसे ध्यानसे पढ़ें। वह कभी दृष्टियोंसे विचारणीय है। यहां मैं उसके अंक पहलूका विचार करता हूँ।

आजकल; खासकर पश्चिममें अंक असी मनोवृत्ति बन गयी है, मानो साम्यवाद और साम्यवादी कोजी अस्पृश्य-सी चीज है, और उनको हमें अपने पास फटकने भी नहीं देना चाहिये। तो अंक छिपकर रहनेवाला साम्यवादी नेता साहस और विश्वासके साथ श्री विनोबा जैसे व्यक्तिको, जिनका वह सरकार बड़ा आदर करती है जो साम्यवादियोंको अपना शत्रु मानती है और जो साम्यवादियोंकी निगाहमें उनका दमन करती है, पत्र लिखता है और विनोबा भी उसे अतनी ही मित्रताके साथ जवाब देते हैं। यह बात उन राजकीय नेताओं और देशोंको, जो राजनैतिक विचारोंमें द्वेषकी सीमाको पहुंचा हुआ मतभेद रखते हैं, अजीब-सी मालूम होगी। अधिकांश देशोंमें, जब कोजी देश किसी दूसरे देशके खिलाफ युद्ध छेड़ता है, तो दोनों देशोंकी जनताको यह सिखाया जाता है कि वे शत्रु-देशके हरअंक नागरिकको अपना निजी शत्रु मानें और उसे पकड़कर अधिकारियोंको सौंप देना या उसे अंकदम मार डालना अपना कर्तव्य समझें। युद्ध न हो रहा हो, सिर्फ सम्बन्ध बहुत खिच गये हों, तब भी उनके आपसी मनोभाव अन्ध असहिष्णुताके होते हैं। पश्चिमके या पश्चिमसे प्रभावित देशोंके लोग आजकल दूसरोंके धर्मके विषयमें काफी आदर या अपेक्षाकी वृत्तिवाले हो गये हैं। लेकिन असहिष्णुताकी उनकी पुरानी परम्परा, जिसके कारण बीसाके बाद कोजी सत्रह सौ वर्ष तक यहूदी, असीामी और मुसलमान पैगम्बरों तथा सन्तों पर और बादमें उन धर्मोंमें पैदा हुअे सुधारकों या अश्रद्धालुओं पर अत्याचार होते रहे, और कभी-कभी तो प्राणदण्ड भी दिया जाता रहा, आज भी चल रही है। लोकराज्यों और साम्यवादी देशोंमें जो आपसी तनाजा है, उसमें वही चीज दिखायी पड़ती है। जिस तरह किसी समय रोमन कैथालिकोंके देशमें प्रोटेस्टेंट होना या प्रोटेस्टेंटोंके देशमें रोमन कैथालिक होना मुश्किल होता था, उसी तरह आज किसी जनतंत्रवादीका रूसमें आजादीसे घूमना-फिरना या किसी साम्यवादीका अमेरिकामें रहना मुश्किल है।

कुछ ही महीने पहले हमने खबरारोंमें पढ़ा था कि अमेरिकामें डॉ० भारतन् कुमारप्पा पर यह संदेह किया गया है कि वे साम्यवादसे सहानुभूति रखते हैं, और असलिये उनके भाषणोंका कार्यक्रम अंकाअंक रोक दिया गया। जिन संस्थाओंने श्री भारतन्को निसंश्रित किया था, वे उनके किन् विचारोंसे नाराज हो गयीं, जिसका विवरण श्री भारतन्के शब्दोंमें ही सुनिये:

“साम्यवादके बारेमें मैंने स्पष्ट कर दिया था कि हम लोग हिंसा और किसी भी तरहके तानाशाही राजतंत्रके खिलाफ हैं। लेकिन मैंने कहा कि उसका लक्ष्य, यानी असी समाज-व्यवस्थाकी स्थापना जिसमें कोजी शोषण नहीं होगा और सम्यताकी सुख-सुविधायें जनताके दुःखी और दलित वर्गको भी भयस्सर होंगी, हर्षमें आता है; और जिसका कारण यह है कि हमारी जनताको अधिकांश

बहुत ही दरिद्र है। यह अंक दुर्भाग्य है कि साम्यवाद यह लक्ष्य अनैतिक और अंकदम हिंसक साधनोंके द्वारा हासिल करना चाहता है। असलिये मैंने कहा कि अगर भारतने साम्यवादियोंके लक्ष्यको स्वीकार किया, तो उसे भिन्न मार्गका, गांधीजी द्वारा सिखाये सत्य और अहिंसाके मार्गका, अवलम्बन करना होगा।

“मैंने उन्हें बताया कि साम्यवादियोंके प्रति भारतके और अमेरिकाके रूखमें यहां अंक बुनियादी भेद है। हम लोगोंकी रायमें साम्यवाद अंक विचार है, जिसका विकास हरअंक देश अपने स्वभावके अनुसार कर सकता है। उसके लिये यह जरूरी नहीं है कि वह रूसी पद्धतिका ही अनुकरण करे; मुमकिन तो यह भी है कि जिसमें उसे रूसका विरोध भी करना पड़े, जैसा कि युगोस्लावियामें हुआ है। लेकिन अमेरिका तो साम्यवादको रूसी साम्राज्यवादके सिवा और कुछ मानता ही नहीं। चूंकि हम साम्यवादको अंक असी चीज मानते हैं, जिसे हम मनचाहा गढ़ सकते हैं, असलिये साम्यवाद हमें अतना डरावना नहीं मालूम होता जितना कि साम्राज्यवाद। सच तो यह है कि उसमें हमारी जनताके विशाल समुदायोंके लिये नयी आशा और नये जीवनका आकर्षण होना भी सम्भव है। लेकिन यदि असा नहीं हुआ और साम्यवाद हमारे यहां रूसी साम्राज्यवादके रूपमें आया, तो मेरा दृढ़ मत है कि वह अशियामें ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। अशियामें आज सर्वत्र राष्ट्रीयताकी ज्वाला सुलग रही है, और वह किसी भी विदेशी सत्ताका फरमां-बरदार होना पसन्द नहीं करेगा। चीन और भारत दोनों विशालकाय देश हैं, उनकी अति प्राचीन परम्परायें हैं, और आज उनमें नया जीवन लहरें मार रहा है। असलिये यह सम्भव नहीं है कि रूस उनमें निगल ले, जैसा कि पिछले युद्धके बाद उसने यूरोपके कुछ छोटे-छोटे देशोंको निगल लिया है। हम लोग अपनी राष्ट्रीय आजादीकी रक्षा प्राणपणसे करनेके लिये कटिबद्ध हैं। मैंने कहा कि जिसे यह डर लगता हो कि रूसी साम्राज्यवादके रूपका साम्यवाद कहीं भारतमें न फल जाय, उसे यह बात याद रखनी चाहिये।”

लेकिन साम्यवादके प्रति जिस असंकुचित और सहिष्णु मनो-भावको अमेरिका जैसा स्वतंत्रताका अनुरागी और लोकराज्यका हामी देश भी सह नहीं सकता!

यह भारतकी प्रणालिका नहीं है। यहां तक कि भारतवासी मुसलमान भी, जो अपनी पुरानी परम्पराके कारण हिन्दुओं और पारसियोंकी अपेक्षा साधारणतः ज्यादा कट्टर और असहिष्णु रहे हैं, भारतीय प्रभावमें आकर अपनी मतान्धतासे अपूर अटने लगे थे। और हिन्दुओंने तो जिस दोषको अपने जीवनसे जितना पहले दूर कर दिया था कि किसी बीते हुअे युगमें हमें उसके रहनेके चिन्ह प्रह्लाद और सुधन्वाकी पौराणिक कहानियोंमें ही मिलते हैं। हिन्दुओंके अतिहासमें सुधारकोंकी — जिनमें कुछ तो अंकदम क्रान्तिकारी थे — अंक अटूट परंपरा चली आयी है। जिसमें उन्हें कुछ सामाजिक विरोध और जुल्म जरूर सहना पड़ा। लेकिन सुधारकोंको दूसरे देशोंमें जो जुल्म सहने पड़े हैं, उनके मुकाबलेमें वह कुछ तहीं था। अगर ब्रिटिश साम्राज्यवादने बीचमें आकर भारतकी मुख्य धर्म-जातियोंमें धर्मान्धताकी आग फिरसे न सुलगायी होती, जिसके फलस्वरूप पिछले कुछ वर्षोंसे हिन्दुओंके आदर और सहिष्णु जीवनमें भी अंक प्रतिगामी पुनरुद्धार (revivalism) की प्रवृत्ति अठ खड़ी हुअी है, तो यह मानना भी कठिन हो जाता कि प्रह्लादकी कहानी वास्तविक जीवनमें कभी घटित हो सकती है। जहां तक मैं जानता हूँ, भारतके अतिहासमें गांधीजीका ही असा पहला

अुदाहरण है, जिसमें बुद्ध और महावीरकी अूचाओका महात्मा अपने ही स्वधर्मियों द्वारा अिसलिये मार डाला गया कि वह अुनकी तरह धर्मान्व, पुराण मतवादी और संकुचित साम्प्रदायिक नहीं था।

विभिन्न राजनैतिक पक्षों और अुनके असूलोंके प्रति भी भारतीय मनोभाव अुतना ही अुदार है। 'साम्यवाद' शब्द सुनकर या 'साम्यवादी' को देखकर हमारे मनमें अेकदम कोअी घृणाका भाव नहीं आता। और यदि साम्यवादी न्याय्य मानव-समाजके अपने बुनियादी विचारों पर अमल करनेमें या अुनका प्रचार करनेमें गुप्त, हिंसक और वंचक अुपायोंका आश्रय न लें, तो अुन्हें भी अपना काम करने और साम्यवादी ढंगके जीवनका प्रयोग करनेकी वही आजादी और रक्षण मिलेगा, जो कि किसी दूसरे राजनैतिक, धार्मिक या सामाजिक संगठनको मिलता है।

अिसका अर्थ यह नहीं है कि सर्वोदय और साम्यवादमें कोअी महत्त्वके फर्क नहीं हैं। जैसा कि विनोबाजीने अन्यत्र कहा है, साम्यवादका असली प्रतिपक्षी लोकतंत्रके बानेमें छिपकर चलनेवाला पूंजीवाद नहीं है, बल्कि गांधीजीका 'सर्वोदय' है। यदि गांधीजीका जीवन और अुनके जीवन-व्यापी प्रयोग व्यर्थ नहीं हो गये हैं, तो सर्वोदय ही अैसा है जो अेक ओर साम्यवाद और दूसरी ओर पूंजीवाद दोनोंको परास्त करनेवाला है। और अिसी तरह भारत और पाकिस्तानको आपसी शत्रुताका अन्त भी अुसीसे होनेवाला है। सैनिक तैयारियां, अेटम और हाअिड्रोजन बम, भड़कीला प्रचार, और अेक-दूसरेको लगातार साशंक रखनेकी कोशिशोंसे साम्यवाद या पूंजीवादका अन्त नहीं होनेवाला है; और न दोनोंका मेल करनेकी 'यूनो' की कोशिश ही तब तक सफल होनेवाली है, जब तक कि अुसको आखिरी शक्ति अेक या अनेक देशोंका सामूहिक सैनिक-बल है। अिसका परिणाम तो यही हो सकता है कि बीच-बीचमें विरामकी सन्धि हो जाया करे और लगातार युद्ध होते रहें। लेकिन निःशस्त्र सर्वोदयकी यह महिमा है कि वह साम्यवाद, पूंजीवाद और सम्प्रदायवाद, आदि अपने सब सशस्त्र प्रतियोगियोंके साथ निःशंक मैत्रीपूर्वक मिल सकता है, अुनकी सुन सकता है और अपनी कह सकता है। यह सर्वोदयकी ही खूबी है।

'आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः' (आत्मा ही अपना मित्र और शत्रु है), यह गीताका वचन है। अिसलिये सर्वोदयमें हम न सिर्फ 'प्यारे मित्र'का ही, बल्कि 'प्यारे शत्रु'का भी सम्बोधन कर सकते हैं। और विनोबाके द्वारा सर्वोदयने अपने अिस प्रिय शत्रु साम्यवादसे अपने व्यवहार पर पुनर्विचार करनेके लिये, अहिसाके शान्तिमय अुपायोंके सामने सच्चा और पूरा समर्पण करनेके लिये और अिस तरह साम्यवादके लक्ष्यसे भी जो ज्यादा गहरी और पूर्ण है, अुस जड़मूलकी क्रान्तिको सिद्ध करनेके लिये आमंत्रण दिया है।

मैं आशा करता हूँ कि यह आमंत्रण व्यर्थ नहीं जायगा।

वर्षा, ६-८-५१

कि० घ० मशरूफ़वाला

(अंग्रेजीसे)

अभिनन्दन

कांग्रेसके महामंत्रीने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीके बंगलौर अधिवेशनमें ता० १५-७-५१ को पास किया गया यह प्रस्ताव भेजा है:

"यह सभा आचार्य विनोबा भावेकी, महात्मा गांधीकी विशुद्ध भावनाके अनुसार की गयी, हैदराबाद राज्यके तेलंगाना प्रान्तकी यात्राकी गहरी कद्र करती है। आचार्यजी अपने साथ अहिसाका पावन संदेश ले गये, और अुन्होंने अुस हिंसा और द्वेषका शमन करनेमें बड़ी मदद पहुंचायी, जिसने कि अुस अत्युद्धित प्रान्तको त्रस्त कर रखा है।"

(अंग्रेजीसे)

'पहली पंचवर्षीय योजना' पर टीका-२

अुद्योग

बड़े अुद्योगोंके क्षेत्रमें व्यक्तिगत साहसको प्रायः पूरी छूट दी गयी है; यहां तक कि अुनकी जो योजना यहां दी गयी है, अुसमें विदेशी व्यापारियों या व्यापारिक कम्पनियों तकको यहां आकर काम करनेका बुलावा दिया गया है। यह नीति खतरनाक है। अेक बार जहां विदेशी 'निहित स्वार्थों' (vested interests) का पांव हमारे यहां जम गया कि फिर अुन्हें हटाना लगभग असम्भव हो जायगा। विदेशी कर्जको जो प्रोत्साहन मिल रहा है, वह विदेशी साम्राज्यवादके प्रवेशके लिये हमारा दरवाजा खोल रहा है। विदेशी पूंजीको देशी व्यापारियोंके साथ साझा कर सकनेकी जो सुविधा दी गयी है, वह भी खतरसे भरपूर है। कहा गया है कि दियासलाओके अुत्पादनमें हम काफी आगे बढ़ गये हैं। जाहिर है कि कहनेवाले यह भूल गये हैं कि अिस व्यापारका अधिकांश 'विमको' के हाथमें है; यह 'विमको' दर असल अेक विदेशी अिजारेदारी (monopoly) है, और वह अिस दिशामें देशी अुद्योगको, कुचलनेके लिये तरह-तरहके अुपाय करती है।

सरकार कृत्रिम खादकी फैक्ट्रियोंके विकासमें जो मदद कर रही है, अुसे भी हम असन्तोषकी दृष्टिसे देखते हैं। अिन रसायनिक खादोंका अुचित अुपयोग हो, अिसकी पहली शर्त यह है कि हमारे पास काफी बड़ी संख्यामें जमीनके जानकार रसायनशास्त्री होने चाहियें, जो प्रत्येक जमीनकी जांच करें और बतायें कि अुसमें कितनी खाद देनी होगी। अैसी सावधानी रखे बिना रासायनिक खादोंका अन्धाधुंध अुपयोग हमारी अुपजाअू जमीनको बरबाद कर देगा और हमें भयंकर आपत्तिके घाट पर ला पटकेगा।

योजना-कमिशनने शक्कर, चावल और वनस्पतिकी मिलोंके साथ रियायतका बर्ताव किया है। ये कारखाने आहारकी वस्तुओंका नाश करते हैं। अिसलिये, खासकर आजकी परिस्थितियोंमें, अुम्मीद तो यह थी कि अुनकी बुराअियोंका अिजहार होगा, और जरूरी हो तो अुन्हें बन्द भी किया जायगा। जनताके स्वास्थ्य और अुचित आहारके लिहाजसे भी कमिशनको चाहिये था कि वह अुनके प्रति कोअी दूसरी नीति अस्तित्थार करता। लेकिन स्पष्ट है कि वह अिन व्यापारोंमें अिनका स्वार्थ है, अुनका मुकाबला करनेके लिये तैयार नहीं है। अिसी सिलसिलेमें यह भी कहना जरूरी है कि खाद्य-वस्तुओं और दवाअियोंके अिज्ञापनों पर सरकारी सहमति और लायसेन्सका नियंत्रण होना चाहिये।

कमिशनने गृह-अुद्योगोंके विकासका समर्थन तो किया है, लेकिन अुसके लिये स्थानीय आयात पर किसी प्रतिबन्धका लगाना जरूरी नहीं माना है। हमारा खयाल तो यह है कि स्थानीय मांग पैदा करनेके लिये यह जरूरी हो जाता है कि बाहरका आयात रोका जाय। गांववालोंके साधनोंमें भी कफायतशारी जरूरी है, ताकि वे अपनी प्राप्त आयका अुपयोग स्थानीय अुत्पादनके काममें कर सकें। अुन्हें बाहरके प्रलोभनोंसे बचाना चाहिये। अगर हम ग्रामीणोंको पुनः संजीवित करना चाहते हैं, तो हमें स्वदेशीकी दृढ़ भावना पैदा करनी होगी।

ग्राम-केन्द्रित अुत्पादनको बढ़ाने और अुसकी मदद करनेके लिये कमिशनने सरकारी खरीद-नीतिकी हिमायत की है, यह बहुत अुचित है।

गांवके कारीगरोंकी अेक मुख्य दिक्कत यह है कि अुनके अुद्योगोंके कच्चे मालका नीलाम होता है। अुदाहरणके लिये, नदियोंके किनारे होनेवाला वह विशेष घास, जिसकी चटाअियां बनती हैं, सरकार छोटी-सी आयके लोभमें नीलामसे बेच देती है, जिसका फल यह होता है कि चटाअियोंका स्थानीय अुद्योग नष्ट हो जाता

है और जापानी चटाओ-अधोग बढ़ता है। इसी तरह कुम्हारको जो मिट्टी चाहिये, वह भी किसी सरकारी ठेकेदारसे खरीदनी पड़ती है, और वह उस पर मुनाफा कमाता है। यह कुम्हारके बरतन-अधोगकी एक बड़ी बाधा है। फिर तरह-तरहके छोटे कर और महसूल हैं, जो मालके यातायातमें मुश्किलें पैदा करते हैं। गृह-अधोगोंके रास्तेमें आनेवाली अिन बाधाओं पर योजनामें पूरा विचार नहीं हुआ है।

घर-निर्माणके सवालका विचार सिर्फ औद्योगिक केन्द्रोंको ही ध्यानमें रखकर किया गया है। लेकिन अिन केन्द्रोंमें घर-निर्माणकी जिम्मेदारी तो अिन अधोगोंकी ही है। सरकारको उस पर नियंत्रण भर रखना चाहिये। सरकार बड़े अधोगोंकी जो कमी तरहकी अदृश्य सहायता करती रहती है, यह उसका एक और अुदाहरण है।

शिक्षा

शिक्षा-प्रणालीका विचार करते हुए रिपोर्टने एक ही सांसमें सीधे-अुलटे विधान किये हैं। सही शिक्षा-प्रणाली क्या होगी, अिस बारेमें उसकी कोअी निश्चित नीति या सिद्धान्त नहीं है। और सब कामोंमें कोअी निश्चित नीति हो या न हो, पर शिक्षाकी तो निश्चित नीति होनी ही चाहिये और उससे यह प्रगट होना चाहिये कि हम राष्ट्रको विकासकी किस राह पर चलाना चाहते हैं। अिस अध्यायमें गांधी-पद्धतिकी बुनियादी शिक्षा, मैकॉलेकी बदनम पद्धतिकी माध्यमिक शिक्षा, और साम्राज्यवादी पद्धतिकी विश्वविद्यालयीन शिक्षा, सबका एक-सा समावेश हुआ है! सबकी निष्पक्ष सिफारिश हुआ है! मसौदेमें सुझायी गयी बहुतसी योजनाओंमें विचारकी अेकसूत्रता नहीं है, उसका यह अेक अुदाहरण है।

राजतंत्र

प्रत्येक राष्ट्र, राष्ट्रीय-जीवनके अनुकूल, अपने लिये अेक विशेष राजतंत्रका विकास करता है। ब्रिटेन अपनी मुख्य आवश्यकताओंके लिये अपने अुपनिवेशों और दूसरे दूर देशों पर निर्भर है। वह अेक साम्राज्यवादी देश है। अिसलिये असे अपने मंत्रि-मंडलमें 'रक्षा', 'अर्थ' और 'विदेश नीति'को मुख्य स्थान देता जरूरी हुआ है। हमने भी अिसी व्यवस्थाका अन्धानुकरण किया है। यह नीति खतरनाक है। वह हमें साम्राज्यवादियोंके रास्ते पर ले जा सकती है। अितिहासमें अेसे देशोंके अनेक अुदाहरण मिलेंगे, जिन्होंने 'सेना'को अतिशय महत्व दिया, और अिसलिये अिनकी बड़ी दुर्गति हुयी; क्योंकि सेनाकी यह अनिवार्य प्रवृत्ति होती है कि 'वह खूद शासक-वर्गका रूप ले लेती है। हमें अपनी वर्तमान व्यवस्थाके अिस अन्तर्हित खतरसे सावधान रहना चाहिये। हमारा देश खेती-प्रधान है और अुसके मंत्रि-मंडलकी रचनामें हमारे शांति-वादी अिरादोंका दर्शन होना चाहिये। अिसका यह अर्थ नहीं कि 'रक्षा' का विभाग होना ही नहीं चाहिये। हमारा मतलब अितना ही है कि वह पुलिसकी ही तरह अेक गौण विभाग होना चाहिये, और अुसके अधिकारीको मंत्रि-मंडलकी सदस्यताका दर्जा नहीं मिलना चाहिये। 'अर्थ' और 'विदेश नीति'के विषयमें भी अैसा ही होना चाहिये। अिस योजनामें हमारे राजनैतिक तंत्रमें किस विभागको कितना महत्व देना चाहिये, अिसका अुझ भी बताया जाना चाहिये।

अैसा किया जाय तो मंत्रि-मंडलके सब विभाग अपने-अपने कामके महत्वके अनुसार अपना योग्य स्थान ले लेंगे, और अुनके महकमोंका संगठन अैसा होगा कि सब अपना-अपना काम बखूबी करेंगे और कोअी किसीके रास्तेमें आकर अड़चन पैदा नहीं करेगा।

सामान्य

अिस कच्ची रूपरेखाके आरम्भिक हिस्सेमें विषयका स्पष्ट प्रतिपादन नहीं है, कोरा क़िताबी ज्ञान और शब्दजाल ही ज्यादा

है। अेक सरकारी दस्तावेजमें स्पष्टता और अर्थघनताके गुणोंकी आशा की जाती है। योजनामें खूद अेक बड़ा दोष है। अुसमें किसी निश्चित जीवन-दृष्टिका अभाव है। अिसका परिणाम यह हुआ है कि पूरी योजनामें शुरूसे अखिर तक कोअी अेक नीति नहीं मिलती। अधिकतर तो 'कहींकी अीट, कहींका रोड़ा' वाली हालत हुयी है। अिसके अलावा, अुसमें जीवनकी कलाके साथ अुसे सुसंगत बनानेके लिये कोअी दृष्टि भी नहीं है। पूरी योजनाका सार यों है कि अुसमें व्यक्तिगत-मालिकीके बड़े अधोगोंकी तरफदारी हुयी है। संक्षेपमें हम कह सकते हैं कि योजनाके कुछ कुछ भाग अच्छे हैं।

(अंग्रेजीसे)

जो० का० कुमारप्पा

अुच्च शिक्षाका माध्यम

[बम्बयी सरकारके मुख्य मंत्रीके अेक सामान्य अिशारेसे हमें मालूम हुआ है कि कॉलेजके शिक्षणमें माध्यमके नाते हिन्दीका अुपयोग करनेके बारेमें सरकार बम्बयी राज्यकी अलग-अलग युनिवर्सिटियोंकी सलाह ले रही है। गुजरात युनिवर्सिटीके वाअिस-चान्सलरके अिसी अाशयके अेक कथनसे अिस बातका समर्थन होता है। वे बताते हैं कि सरकारने माध्यमके तीर पर हिन्दीका अुपयोग करनेकी सूचना की है। मैं नहीं मान सकता कि सरकार गुजरातीको अेक और 'रखकर हिन्दीको माध्यम बनानेकी सूचना करने जैसी गंभीर भूल करेगी। राष्ट्रभाषाके नाते हिन्दीका अुपयोग करना और अुसका ज्ञान होना तथा हिन्दीको शिक्षाका माध्यम बनाना, दोनों बिलकुल भिन्न बातें हैं। अिस सारे सवाल पर विभिन्न दृष्टियोंसे गंभीर विचार करना जरूरी है। गुजरात युनिवर्सिटी कमेटीकी रिपोर्ट (१९४८-४९) के साथ जोड़ी हुयी मेरी विरोध-टिप्पणीमें पेश किये अुसे अपने कुछ मन्तव्य (पैरा १९० से आगे) में नीचे देता हूँ। आज यह प्रश्न अुठा है, अिसलिये अुसके सम्बन्धमें अपने विचार यहां फिरसे अुद्धृत करनेके लिये पाठक मुझे क्षमा करेंगे।

— म० देसाजी]

यह ध्यान देने लायक बात है कि शिक्षाके माध्यमका प्रश्न हिन्दुस्तानमें आधुनिक शिक्षाके प्रश्नकी खास अुलझन बना हुआ है। सन् १८३५ में यह शिक्षा शुरू हुयी, तभीसे यह प्रश्न सरकारी और गैरसरकारी मंडलोंके समर्थ और बड़े विचारकोंके मनको निरन्तर मथता रहा है। आज हम देखते हैं कि यह प्रश्न सबसे आगे आ गया है। शायद १८३५ का अरसा अिसका अुपवाद माना जा सकता है। फर्क अितना ही है कि १८३५ में अिस प्रश्नके मुद्दों पर निर्णय करनेकी जिम्मेदारी विदेशियों पर थी, जब कि आज स्वतंत्र प्रजाके नाते हमें ही अिसका निर्णय करना है। आज हम जो निर्णय करेंगे, वह ज्यादा नहीं तो अुस समय जितना ही महत्वपूर्ण और युगप्रवर्तक सिद्ध होगा।

शिक्षाका सच्चा माध्यम बालककी भाषा ही हो सकती है, यह सिद्धान्त सब जगह स्वीकार किया गया है। अिसके बारेमें कोअी प्रश्न ही खड़ा नहीं होना चाहिये। लेकिन दुःखकी बात है कि शिक्षाके अिस निश्चित और ठोस सिद्धान्तको अेक तरफ रखकर अेक पक्ष यह हिमायत करता है कि अुच्च शिक्षाका माध्यम राष्ट्रभाषा या संघभाषा होनी चाहिये। सन् १८३५ में देशके सामने जैसी परिस्थिति खड़ी हुयी थी (अंग्रेजी बनाम देशी भाषाओं), लगभग वैसी ही परिस्थिति अब भी खड़ी हुयी है; और हिन्दुस्तानी बनाम प्रान्तीय भाषाओंके बीच चुनाव करनेकी बात हमारे सामने खड़ी की गयी है। सारे हिन्दुस्तानमें अुचे वर्गोंके लिये सार्वत्रिक राजमान्य माध्यमके रूपमें काम देनेवाली अंग्रेजी भाषाकी संकास्पद तुलनाके आधार पर अिस विचारधाराके लोग मुख्यतः भारतकी अकताके नाम पर यह दलील करते हैं।

बेशक प्रान्तवाद, बुरी चीज है। लेकिन क्या यह दलील की जा सकती है कि वह वाद प्रान्तीय भाषाओंके कारण पैदा होता

है? हरगिज नहीं। आज हमारे पास अंग्रेजीके सामान्य माध्यमके होते हुये भी क्या यह बात मौजूद नहीं है? यह तो तय है कि युनिवर्सिटीके पास शिक्षाका कोअी माध्यम होना चाहिये। और यदि यह निश्चित सिद्धान्त हो कि वह माध्यम मातृभाषा ही होनी चाहिये, तो फिर भीमानदारीकी तरह यही सत्रसे अच्छी नीति और सबसे निश्चित मार्ग कहा जा सकता है। राष्ट्र या जनतासे संबंध रखनेवाली बातोंमें अुसका भविष्य सत्यके हाथमें सौंपना चाहिये, न कि अुसके अुपरसे वास्तविक दिखाजी देनेवाले झूठे रूपोंके हाथमें। यही हमेशा अुत्तम नीति और सच्ची बुद्धिमानी है।

पहले तो अुच्च शिक्षाके लिये माध्यम तय करनेका सवाल केवल अंग्रेजीकी जगह दूसरी भाषा खोज निकालनेका सवाल नहीं है, ताकि वह दूसरी भाषा जैसे अब तक अंग्रेजी करती आजी है वैसे विविध प्रान्तीय भाषाओं पर हावी हो जाय। यह नजी हावी हो बैठनेवाली भाषा अखिल भारतकी सर्वमान्य भाषा हो, तो जिससे अुसका स्वभाव कोअी बदल नहीं जाता। अुसी तरह, जिससे गुजरातीका, जिसका दावा सब तरफसे स्वीकार किया गया है, स्थान हजम कर लेनेके अखिल भारतकी सर्वसामान्य भाषाके मूलतः झूठे दावेमें भी कोअी फर्क नहीं पड़ता।

दूसरी अेक बातका भी ध्यान रखना चाहिये। किसी प्रजाके लोकशाही और संस्कृतिके विकासके इतिहास पर हम निगाह डालेंगे, तो पता चलेगा कि अुंचे वर्गोंकी अर्थात् अुपरी सिरके लोगोंकी भाषा, जो प्रादेशिक देशी भाषाओं पर अपना प्रभुत्व रखती थी, का स्थान प्रादेशिक भाषायें लेती हैं; और समय बीतने पर ये प्रादेशिक भाषायें अुतनी ही प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेती हैं। युरोपमें पुनरुत्थान और सुधार-युगके बादकी सदियोंमें लेटिनकी जगह युरोपीय भाषाओंने ले ली, और वे ही आज अपने-अपने प्रदेशकी युनिवर्सिटीयोंकी माध्यम बनी हुयी हैं। साधारण आदमीको अुंचे वर्गोंके साथ समाज-जीवनमें जो हिस्सा लेना है, अुसे जानने और करनेकी आवश्यकता ही जिस क्रांतिकारी घटनाका कारण बनी है। संस्कृतके खिलाफ पाली, प्राकृत और 'भाखा' के आन्दोलनको भी देखिये। पिछली ६ या ७ सदियोंके अरसेमें विकसित बारह-पन्द्रह भारतीय भाषायें, जिनका व्यवहार देशके कुछ हजार नहीं, बल्कि करोड़ों लोग करते हैं, इसी ऐतिहासिक प्रक्रियामें से जनमी हैं। फारसी और अंग्रेजी भाषाके प्रभुत्वके बुरेसे बुरे दिनोंमें भी वे सब टिकी रहीं। सच पूछा जाय तो जिन दोनों भाषाओंका प्रभुत्व होते हुये भी अुन्होंने अिनसे जरूरी पोषण लेकर और समृद्ध बनकर अपनी जीवनशक्ति सिद्ध कर दिखायी है।

लेकिन कुछ लोग अैसे भी हैं, जो राष्ट्रभाषाको माध्यम बनानेके अुत्साहमें बहकर यहां तक कहने लगे हैं कि अैसा करनेमें प्रान्तीय भाषायें अन्तमें लुप्त भी हो जायं तो कोअी परवाह नहीं। यह हमारी खुशकिस्मती है कि सच्ची राष्ट्रियता हबसे यह भोग मांगती ही नहीं। जैसा कि हम अुपर देख चुके हैं, जिन भाषाओंके विकासको रोक नहीं जा सकता। और यह केवल संभव ही नहीं, बल्कि हितकर और आवश्यक भी है कि वे सब हिन्दुस्तानीके साथ अपनेको भी अेक राष्ट्रीय तानेबानेमें ओतप्रोत कर लें। अपने गलत निर्णयके कारण हमारी भाषाओंके बीच पारिवारिक कलह खड़ा नहीं करना चाहिये। फिर भी यदि राष्ट्रभाषाका दुरु-पयोग करके अंग्रेजीकी जगह अुसे कायम किया जायगा, तो निश्चित है कि प्रादेशिक भाषायें आजकी अविकसित हालतमें बनी रहेंगी और युनिवर्सिटीके स्तर तक नहीं पहुंच सकेंगी — जिस स्तर तक पहुंचनेका अुनका न्यायसंगत दावा और जन्मसिद्ध अधिकार है। क्योंकि अंगर हम अपनी सारी पढ़ाओ, शिक्षण और शोधकार्यके माध्यमके रूपमें अुनका अुपयोग न करें, तो निश्चित है कि वे अुस हद तक अविकसित ही रहेंगी। मैं अुपर बतानेका प्रयत्न किया है, अुसके मुताबिक यदि सचमुच अैसा हुआ, तो यह बड़े

संकटकी बात होगी और अुससे लोकशाही और शिक्षाका विकास जरूर रहेगा।

जिसके अलावा, जिससे हिन्दुस्तानी और जिन भाषाओंके बीच अैसा तनाव पैदा होगा, जो सचमुच बड़ा खतरनाक साबित होगा। दरअसल यह तनाव और खींचतान संकुचित प्रान्तवादको अुत्तेजन देगी, जिसका माध्यमके रूपमें राष्ट्रभाषाकी हिमायत करनेवालोंको खुद ही जितना बड़ा डर है।

स्वीकार करनेके लिये सर्वमान्य जैसी कोअी राष्ट्रभाषा तैयार ही होती, तब तो हिन्दुस्तानीको माध्यम बनवानेवालोंकी बात समझी भी जा सकती थी। लेकिन दरअसल हालत यह है कि हमारे राष्ट्रीयत्वके साथ-साथ हमारी राष्ट्रभाषाको भी अमी विकास करना है। राष्ट्रभाषा तो हमारी राष्ट्रीय अेकताका प्रतीक — खुद अुसका आविष्कार ही बननेवाली है। परन्तु जिस बारेमें भी संस्कृतमयी हिन्दी तथा हिन्दुत्वकी भावनाके पुनरुद्धारके संकुचित विचारसे अपने संकुचित मूल्य स्थापित करने और सच्ची राष्ट्रीय प्रगतिको रोकनेका प्रयत्न किया जाता है।

प्रान्तीय भाषायें अैसे विचारसे मुक्त हैं। अलबत्ता, यह सच है कि वे पूरी तरह विकसित नहीं हैं। परन्तु यह हालत तो आज हिन्दीकी भी है। परन्तु जिन सब भाषाओंका अेक लक्षण यह है कि अुनका किसी अेक भाषाके विरुद्ध प्रतियोगिताका दावा नहीं है; और अुनमें से हरअेक अपने ढंगसे सबके संयुक्त और सामान्य प्रयत्नसे युनिवर्सिटीके स्तर तक पहुंचनेके लिये तैयार है। राष्ट्रभाषाको अंगर कुछ करना ही हो, तो अुसे जिस संयुक्त प्रयत्नमें पूरकका स्थान लेना चाहिये; अुसे प्रान्तीय भाषाओंके साथ संघर्ष नहीं करना चाहिये या अुनसे होड़ नहीं लगानी चाहिये।

जिस जगह यह याद रखना चाहिये कि राष्ट्रभाषाके आन्दोलनकी बुनियाद समस्त देशके लोगोंको दिये गये जिस वचनमें है कि हिन्दुस्तानी भाषा "प्रान्तीय भाषाओंका स्थान ले, अैसा नहीं सोचा गया है; बल्कि यह अिरादा रखा गया है कि वह अुनकी पूरक बने और आन्तरप्रान्तीय संबंधके लिये काममें ली जाय"। (गांधीजी) अब अंगर हम अपने जिस निश्चयको छोड़कर प्रान्तीय भाषाओंको अुनके आदर और प्रतिष्ठाके पदसे हटायें — अर्थात् हर प्रकारके शिक्षणका माध्यम बननेके अुनके खुले हकको अुनसे छीनें — और अुस जगह राष्ट्रभाषाको बैठायें, तो राष्ट्रभाषाके आन्दोलनकी सारी अिमारत ही अेकदम ढह जायगी और हमारा अेक पीढ़ीसे भी ज्यादाका प्रयत्न धूलमें मिल जायगा। और अुसका नतीजा यह होगा कि अंग्रेजी चालू ही रहेगी।

(गुजरातीसे)

तालाब और बांध

सरकारकी पंचवर्षीय योजनामें अधिक ध्यान खींचनेवाली चीज है करोड़ों रुपये खर्च करके बांधे जानेवाले कुछ नदियोंके बांध। ये बांध अिजीनियरीके महान साहस कहे जा सकते हैं। यह काम पूरा हो जानेसे अेक तरहकी हमारी वाहवाही होगी और शायद विदेशोंमें हमारा नाम भी बढ़ेगा। ये बांध बंध जायं, तो देशकी लाखों अेकड़ जमीनमें सिंचाई हो सकेगी। जो पानी बहकर समुद्रमें मिल जाता है, वह अिकट्ठा किया जा सकता है। अुससे बिजली भी मिलेगी।

जिस तरह यह विचार अच्छा है। लेकिन अुसकी मर्यादा भी है, यही हमें याद रखना चाहिये। सिंचाईके लिये पानी मुहैया करनेके दूसरे रास्ते भी हैं और अुन पर बड़ी योजनाओंके बिना भी अमल किया जा सकता है। जैसे, अनुकूल जगहों पर बड़े तालाब भी यह काम दे सकते हैं। छोटी-छोटी नदियोंमें पाल बांधकर भी पानी अिकट्ठा किया जा सकता है। जिस तरहकी योजनाके लिये अनेकों स्थान सोचे जा सकते हैं। जिस काममें लोगोंको

शामिल करके अुस जगहकी आबादीका' आलस्य और बेकारी दूर की जा सकती है। अलबत्ता, जिस काममें भी कुशल अिजीनियरोंको विस्तृत योजना बनाकर अुसके अमलके लिये ब्यारे-वार आयोजन करना पड़ेगा। पर जिसमें बहुत बड़े अिजीनियरोंकी जरूरत नहीं होगी। न बड़े-बड़े यंत्रोंकी जरूरत होगी, न बड़े भारी मेमारी कामकी जरूरत होगी। बेशक, जिस काममें भी करोड़ों रुपये खर्च जा सकते हैं। लेकिन विकेंद्रित ढंग पर और लोगोंका व्यापक सहकार लेकर। अुसमें त्रिशालताकी चमक शायद नहीं होगी; फिर भी काम तो होगा ही और लोगोंकी तालीमका अमूल्य लाभ भी मिलेगा। संभव है, यह सुझाव मिलके सामने चरखे जैसा लगे। और कुछ हद तक अैसा कहना सच भी है। जिसमें भी चरखे या खादीका अर्थशास्त्र और मानवदृष्टि है। जिसलिये योजना बनानेवालोंको जिस तरफ भी ध्यान देना चाहिये था। बड़े-बड़े बांध बांधना ठीक हो, तो अुनके साथ अैसी छोटी मालूम होनेवाली लेकिन खूब कीमती योजनाको भी गूथ देना चाहिये। जिसकी अेक खूबी यह है कि इसके लिये जिलावार योजनायें बनाकर अुनमें लोगोंकी दिलचस्पी पैदा की जा सकती है। जिसमें आखिरमें जनताकी शक्ति भी बढ़ती है।

अहमदाबाद, २-८-५१

मगनभायी देसाजी

(गुजरातीसे)

राजनैतिक असहिष्णुता

अग्रलेखमें मैंने जिक्र किया है कि आजके युगमें हिन्दू समाजमें असहिष्णुता और धर्माघातका अेक नया दौर आया है। मुझे यह जानकर खेद हुआ कि यह प्रवृत्ति कांग्रेसमें भी व्याप्त हो गयी है और हमारे राजनैतिक जीवनमें वह बढ़ती-फैलती जा रही है। मुझे मालूम हुआ है कि कुछ समयसे जगह-जगह स्थानीय राजनैतिक दलोंमें अकसर अपने सदस्योंको अैसी सूचनायें दी जाती हैं कि वे प्रतिपक्षके राजनैतिक नेताकी सभामें न जायें, अुनके आयोजनोंमें भाग न लें और न अैसे किसी कार्यक्रममें ही सहकार करें, जिसकी व्यवस्था अुसके द्वारा की गयी हो — भले वह कार्यक्रम रचनात्मक ही क्यों न हो। कोजी कांग्रेसका आदमी प्रतिपक्षके किसी व्यक्तिको मेहमानकी तरह स्वागत भी न करे, अैसी कोशिश भी होती है। गांधीजी जब पहली बार बिहार गये, तब अंग्रेजी नौकरशाही अितनी असहिष्णु थी कि आचार्य कृपलानीको गांधीजीको अपने घरमें रखनेकी हिम्मत दिखानेके लिये अपनी प्रोफेसरशिप छोड़नी पड़ी थी। यह घटना सन् १९१७ की है। सब लोग जानते हैं कि तबसे लगातार वे गांधीजीके साथ रहे। कुछ ही महीने(पहले तक वे कांग्रेसी ही थे। अभी कांग्रेस अध्यक्षका जो पिछला चुनाव हुआ, अुसमें प्रगट हुआ कि लगभग आधी कांग्रेसका और प्रधान मंत्रीका भी विश्वास अुन्हें प्राप्त था। कांग्रेसके मुखियों (हाजी कभाण्ड) ने अुनसे कांग्रेसमें ही बने रहनेका अनुरोध भी किया। पर अुन्होंने अलग होनेका निर्णय किया और प्रगट रूपसे यह अिच्छा जाहिर की है कि वे अगले चुनावोंमें मौजूदा कांग्रेस सरकारको हटाना चाहते हैं। अुनका यह निर्णय सही हो या गलत, अुसमें सयानपन हो या बेवकूफी, और अपनी कोशिशमें वे कामयाब हों या नहीं, यह अलग सवाल है। लेकिन अुन्होंने जो रास्ता लिया है, वह पूरी तरहसे लोकशाहीका रास्ता है; और अगर वे कांग्रेसका विरोध कर रहे हैं, तो अुसका यह अर्थ नहीं है कि वे हिन्दू स्वराज्यके शत्रु बन गये हैं। ठीक अुसी तरह जैसे सन् १९१७ में गांधीजी ब्रिटिश शासन पद्धतिका विरोध करते हुअे भी ब्रिटिश राजके शत्रु नहीं थे।

आज सन् १९५१ में वही परिस्थिति दुहरायी जा रही है। वे ही मौजूदा सरकारके राजनैतिक विरोधी हैं और यह सरकार अुनके खिलाफ अुसी नीतिका अवलम्बन कर रही है, जिसका अवलम्बन

ब्रिटिश सरकारने गांधीजी और अुनके साथियोंके खिलाफ तब किया था। जहां कहीं भी वे जाते हैं, सी० आजी० डी० के चर अुनका पीछा करते हैं, पुलिसके आदमी अुनकी सभाओंमें कुर्सी-टैबल लगाकर अुनके भाषणकी रिपोर्ट लिखते हैं, मानो लोगोंको सूचित करना चाहते हों कि अुन्हें सरकार शंकाकी निगाहसे देखती है। कांग्रेस संस्थाओंको अैसे परिपत्रक भेजे जाते हैं कि लोगोंसे कहो कि वे अुनकी सभाओंमें न जायें। मुझे मालूम हुआ है कि अुनके अेक दौरमें स्थानीय कांग्रेसियोंने जिस बातका ध्यान रखा कि कोजी कांग्रेसी अुन्हें अपना मेहमान न बनाये। अेक स्थानीय रचनात्मक संस्था द्वारा अुन्हें संस्थाका मुआजिना करनेके लिये बुलाने पर अिन लोगोंने अपनी नाराजी भी जाहिर की।

मैं अैसा नहीं मानता कि चोटीके नेता जिस व्यवहारको मान्य करते हैं। मंत्री लोग तो अुनका बहिष्कार नहीं करते। लेकिन छोटे-छोटे नेता और अखबार जिस तंगदिलीको बढ़ावा देते हैं। यह असहिष्णुता दिलके छोटेपनकी सूचक है। दूसरी विचारधाराओंके साथ जिस तरह पेश आनेकी मनोवृत्ति भारतीय खानदानियतकी निशानी नहीं है। अभी-अभी तक अैसे कअी परिवार रहे हैं, जिनमें परिवारका मुखिया अुदार मतवादी है, अुसका लडका कांग्रेसी है, और पौत्र-पौत्रियोंमें कोजी गांधीवादी है, तो कोजी समाजवादी या साम्यवादी रायका अनुयायी — यहां तक कि सम्प्रदायवादी भी। लेकिन सबके सब अुसी अेक घरमें शांतिपूर्वक रहते रहे हैं। यदि कांग्रेसी या गांधीवादी सदस्यने आज्ञाभंगके आन्दोलनमें भाग लिया, तो अुसने व्यक्तिशः अुसका फल भोगा; और यदि सम्प्रदायवादी या साम्यवादी लडकेने किसी हिंसक कार्रवाजीमें हिस्सा लिया, तो अुसने भी अुसका फल व्यक्तिशः ही भोगा। परिवारका यह मुखिया राज्यका मंत्री या शासनका बड़ा अधिकारी ही क्यों न रहा हो, अुसके पुत्रने भी सजा भोगी। अुदाहरणके लिये, डॉ० पी० सुब्बरायण्के लडकेने। लेकिन यह सजा किसी खास विचारधारामें अुसका विश्वास होनेके कारण नहीं, बल्कि कानूनका भंग करनेके लिये दी गयी। और अुसने सजा पायी तो घरके लोगोंने अुसे घरसे निकाल नहीं दिया।

कांग्रेसी लोगोंकी अगर कृपलानीजीसे हर सवाल पर पटती नहीं है तो न सही। मैं भी अुनके साथ कअी सवालों पर अेकराय नहीं हूँ। लेकिन जिस बातसे अिनकार नहीं किया जा सकता कि कांग्रेसको, किसी और कारणसे नहीं तो लोगोंके मत लेनेके लिये ही, वे भारी बुराजियां, जिनके खिलाफ आचार्य कृपलानी अपनी आवाज अितने जोरसे बुलंद किये जा रहे हैं, दूर करनी पड़ेगी। क्या यह कम दुःखकी बात है कि साठ बरसकी पुरानी कांग्रेसने अितने बड़े पैमाने पर और अितनी जल्दी अपनी प्रतिष्ठा खो दी, और गांधी टोपी व खादी आम लोगों द्वारा भ्रष्टाचार, बेअिमीनी और दूसरी कअी बुराजियोंका प्रतीक मानी जाने लगी है?

लेकिन कांग्रेस अपने विरोधियोंके हमलोंसे या मित्रोंकी सलाहसे लाभ अुठावे या न अुठावे, सारी राजनैतिक संस्थाओंको जिस संकुचिततासे बचनेकी सावधानी रखनी चाहिये। यह संकुचितता तो जात-पातका ही अेक बदला हुआ रूप है।

वर्षा, १-८-५१

कि० घ० मशरूवाला

(अंग्रेजीसे)

विषय-सूची	पृष्ठ
डांगे-विनोबा पत्रव्यवहार	२१७
कोढ़-कामकी तालीम	२१९
साम्यवादके बारेमें	२२०
'पहली पंचवर्षीय योजना'	
पर टीका — २	
अुच्च शिक्षाका माध्यम	२२१
तालाब और बांध	२२२
राजनैतिक असहिष्णुता	२२३
टिप्पणी :	२२४
अभिनन्दन	२२५